CPI(M)

जन जोहार झारखण्ड

अंक–06 मासिक बुलेटिन नवम्बर 2022

संपादकीय ....

झारखंड में केंद्र सरकार के इशारे पर जिस तरह ईडी, सीबीआई और राजभवन द्वारा हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है उसके पीछे आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच से ज्यादा हेमंत सोरेन पर दवाब बढाना है ताकि वे भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर दें. क्योंकि जिस प्रकार खनन लीज मामले मे भाजपा की शिकायत पर राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग से राय मांगी और आयोग ने भी अति सक्रियता दिखाते हुए अपने विशेष दुत को मुख्यमंत्री के पास नोटिस तामिल कराने के लिए भेज दिया. जिसमें सुनवाई के बाद निर्वाचन आयोग ने अपनी राय सील बंद लिफाफे मे पिछले 25 अगस्त को ही राजभवन भेज दिया था. राज्यपाल द्वारा जिसे अब तक दबा कर रखा गया है. मीडिया द्वारा पूछे जाने पर उनके द्वारा कहा गया कि श्लिफाफे पर गोंद इस प्रकार चिपकाया गया है कि लिफाफा खुल नहीं रहा हैश् बाद मे अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान उन्होंने झारखंड मे 'एटम बम' का राजनीतिक धमाका होने और निर्वाचन आयोग से सेकेंड ओपिनियन लिए जाने की बात बोलकर अपनी षडयंत्रकारी भूमिका को उजागर कर दिया है.

कुल मिलाकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूरे देश मे उसकी हां में हां नहीं मिलाने वाली विपक्ष की निर्वाचित सरकार को गिराने की घिनौनी साजिश में लगी हुई है. ताजा घटनाक्रम मे झारखंड, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना की निर्वाचित राज्य सरकारें इनके निशाने पर है. इसके लिए केंद्र सरकार, ईडी, ईसी, सीबीआई और राज्यपाल का इस्तेमाल कर अपनी साजिशों को अमली जामा पहनाने के के षडयंत्र मे लगी हुई है. भाजपा का यह हथकंडा संविधान में उल्लेखित हमारे देश के फेडरल चरित्र को कमजोर किए जाने की सोची समझी चाल है जिसका डट कर विरोध करना होगा. क्योंकि यदि किसी पर कोई आरोप है तो प्रक्रिया के अनुसार कानून अपना काम करेगा लेकिन जनादेश से निर्वाचित सरकार को गिराने की भाजपा की साजिश को झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी. □

धार्मिक अनुकूलन की प्रक्रिया

एक नोबेल विजेता रूसी वैज्ञानिक थे ईवान पेट्रोविच पावलोव। शरीर क्रिया विज्ञान पर एक रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते पर प्रयोग किये।

उन्होंने कुत्ते को प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों में रखा और उसके मुंह में नलियों के द्वारा एक ऐसा यंत्र फिट किया जो उसके मुख में उत्पन्न होने वाली लार की मात्रा को माप सके।

पावलोव के इस मशहूर प्रयोग को समझने से पूर्व कुछ बातें समझनी होंगी जिससे उनका प्रयोग समझने में आसानी होगी।

जीव धारियों के अनेक प्राकृतिक गुणों में से एक गुण है कि वे प्राकृतिक उद्दीपन /के विरुद्ध प्रतिक्रिया करते पाए जाते हैं, जैसे पैदल चलते समय आपके पैर में कोई कांटा चुभ जाए तो आपका पैर मस्तिष्क के बिना सोचे समझे ऊपर उठ जाएगा। यहां कांटा उद्दीपन है और पैर का उठ जाना उस पर आपकी प्राकृतिक प्रतिक्रिया जैसे किसी बच्चे का हाथ गर्म तवे पर पड़ जाए तो वह फौरन प्रतिक्रिया स्वरूप अपने हाथ को उस गर्म तवे से दूर खींच लेगा। यहां गर्म तवा उद्दीपन है और हाथ खींच लेना प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। जैसे आप किसी अच्छे रेस्तरा के पास से गुजरें या किसी अच्छे चाट वाले की दुकान के पास से गुजरें और उसके भोज्य पदार्थों की उड़ती खुशबू को आपकी नाक ग्रहण करे और आपके मुंह में पानी आ जाये तो यहां भोजन की खुशबू प्राकृतिक उद्दीपन है और मुंह में पानी आ जाना हमारी प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। हमारा रोजमर्रा का जीवन ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है।

पावलोव का प्रयोग जीवधारी के उद्दीपन के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने की प्राकतिक क्षमता पर आधारित था। प्रयोग के दौरान पावलोव अपने पालतू कुत्ते के सम्मुख उद्दीपन के रूप में भोजन लाते थे और भोजन सामने आते ही कुत्ते के मुंह में प्राकृतिक प्रतिक्रिया के रूप में लार आ जाती थी। पावलोव ने काफी दिनों तक ये प्रयोग जारी रखा। अब कुत्ता भूखा न होने पर भी सामने भोजन को देखते ही लार निकालने की प्रतिक्रिया देने में अभ्यस्त हो गया था।

कुछ दिनों के बाद पावलोव ने एक बदलाव किया। अब खाना दिखाने के साथ एक घंटी भी बजानी शुरू कर दी। यानि अब वे एक प्राकृतिक उद्दीपन भोजन के साथ एक अप्राकृतिक उद्दीपन घंटी भी बजाया करते थे और कुत्ते के मुंह में प्राकृतिक प्रतिक्रिया स्वरूप लार आ जाती थी। धीरे–धीरे पावलोव ने कुत्ते को भोजन दिखाना बन्द कर दिया बस घंटी बजा देते थे जो कि एक अप्राकृतिक उद्दीपन था और उन्होंने आश्चर्यजनक रुप से देखा कि अब सिर्फ घंटी बजने से ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। उन्होंने इस प्रयोग में घंटी की जगह एक बिजली के बल्ब को जला कर देखा। नतीजे फिर वैसे ही आये।

उनके इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला कि जीवधारियों को प्राकृतिक उद्दीपन के साथ अगर एक अप्राकृतिक उद्दीपन भी दिया जाए तो जीवधारी वैसी ही प्राकृतिक प्रतिक्रिया करते हैं। इस दौरान अप्राकृतिक उद्दीपन के साथ प्रकृतिक प्रतिक्रिया का ऐसा अनुकूलन और युग्मता हो जाती है कि अगर अगर धीरे–धीरे प्राकृतिक उद्दीपन को हटा लिया जाए और मात्र अप्राकृतिक उद्दीपन ही जीवधारी को दिया जाए तो वह उस अप्राकृतिक उद्दीपन के प्रति भी प्राकृतिक प्रतिक्रिया करता दिखाई देता है।

शरीर क्रिया विज्ञान के लिए किया जा रहे इस प्रयोग ने आगे चल कर मनोविज्ञान के लिए अपनी विश्व–प्रसिद्ध ''थ्योरी ऑफ लर्निंग ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग'' उपलब्ध कराई। ये वैज्ञानिक

शेष पेज 3 पर .....

महिलाएं और वर्ग संघर्ष

भाजपा नीत केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण चौतरफा आर्थिक–सामाजिक संकटों में घिरे हमारे देश में समाज व व्यवस्था की अन्य बदहालियों के साथ महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। देश के धर्मिक गुरुओं व अन्य रूढ़िवादी राजनेताओं ने भी इन प्रतिगामी ताकतों को अंधा समर्थन दिया है और ऐसे जघन्य अपराधियों को बचाव का रास्ता भी मुहैया कराया है। इसके खिलाफ उदारपंथी राजनीतिज्ञों, सिविल सोसाइटी तथा समाज सेवकों द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न अभियान सतही ही साबित हुए हैं।

वर्तमान समाज की सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीति रिवाजों में पितृसत्तात्मक मानसिकता तथा पुरूष श्रेष्ठतावादी अवधारणा का प्रभुत्व कायम है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों व हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए पारित अनेक कानून बने हैं लेकिन तमाम कानूनों के बावजूद, महिलाओं की दशा में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है और शोषित वर्गों से ताल्लुक रखने वाली बहुसंख्यक महिला आबादी के जीवन की परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ है। बेतहाशा बढ़ते नृशंस बलात्कार और घरेलु हिंसा के साथ ये कामगार महिलाएं बेकारी, छंटनी, आय विहीन श्रम और बढ़ती आय असमानता द्वारा अमानवीय शोषण का शिकार हैं। वे काम की जगह पर, समाज में तथा परिवार में पुरूष श्रेष्ठतावादी रवैयों तथा यौन उत्पीड़न का शिकार बनती है। इसलिए औरतों के उत्पीड़न को महज लैंगिक सवाल तक सीमित कर देना, उनकी समस्याओं का हल नहीं है और ना ही लैंगिक आधार पर होने वाले इस शोषण के सामाजिक–आर्थिक मूलाधार को समझे बिना उनकी मुक्ति की कोई रणनीति बनाई जा सकती है इन समस्याओं से मुक्ति के लिए किए जाने वाले संघर्ष में वर्गीय तथा लैंगिक सवालों के बीच के अन्तर सबंधों को समझना बहुत जरूरी है।

आज देश में राजनीति, बिजनेस, कला तथा समाज के अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान व पकड़ बनाने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जिनमें अधिकतर शासक वर्ग अथवा मध्य वर्ग की हैं। उनकी समस्याएं, संकट व लक्ष्य मेहनतकश कामगार महिलाओं से पूरी तरह अलग हैं। यदि किसी निम्न वर्ग से कोई महिला इस सामाजिक–आर्थिक ढांचे के भीतर ऊपर उठती है तो वह अक्सर उच्च वर्ग का हिस्सा बन कर अपने मूल वर्ग से विलग हो जाती है।

भौतिक तथा सामाजिक परिस्थितियां ही चेतना का निर्धारण करती है, न कि चेतना इन परिस्थितियों को तय करती है. उदारवादी मानसिकता की समस्या यह है कि ये महिला को एक माल तथा प्रदर्शनकारी विज्ञापन मानने की सोच से मुक्त नहीं हो पाती है। यदि धार्मिक मत महिलाओं को पर्दे में रखने के पक्ष में है और उन्हें एक सम्पत्ति की तरह मानते हैं, तो इसके समानान्तर उच्च वर्ग महिलाओं को अपना व्यापार व मुनाफा बढ़ाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। यदि औरतों का प्रत्यक्ष दमन पाशविक है, तो मुनाफे के लिए माल बेचने हेतु उनकी अर्द्धनग्न तस्वीरों का विज्ञापन क्या उनकी मुक्ति का तरीका है? महिलाओं के साथ होने वाला भेद भाव दरअसल लालच और लोभ की अर्थव्यवस्था द्वारा स्थापित सामाजिक संबंधों से पनपता है। यह संकीर्ण दृष्टिकोण उस सामाजिक मनोविज्ञान में गहरे बैठा हुआ है जिसमें उनका पालन पोषण होता है और उन भौतिक परिस्थितियों को, जिन पर यह सामाजिक–आर्थिक ढांचा टिका हुआ है, नष्ट किए बिना इस दृष्टिकोण से निजात नहीं पाया जा सकता।

शेष पेज 3 पर .....

सीटू का 7 वां राज्य सम्मेलन 12 – 13 नवम्बर को जमशेदपुर में

सीटू का दो दिवसीय राज्य सम्मेलन लौह नगरी और पूर्वी भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहे जमशेदपुर में आयोजित होगा। सम्मेलन के अवसर पर एक जूलूस निकाला जाएगा जिसके बाद हाल मीटिंग होगी।

इस सम्मेलन में कोयला, स्टील, बाक्साइट, पत्थर, खानन, बीडी, बिजली, निर्माण, ट्रांसपोर्ट, तांबा, अल्मुनियम और भारी उधोग समेत विभिन्न परियोजनाओं के स्कीम वर्कर, सेल्स प्रमोशन इम्पलाईज और गिग वर्कर्स के बीच काम कर रहे सीटू से सम्बद्ध 54 यूनियनों के 378 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ये प्रतिनिधि सम्मेलन के सांगठनिक सत्र मे महासचिव के प्रतिवेदन पर चर्चा कर इसे समृद्ध करते हुए आगामी तीन वर्षों के लिए नए नेतृत्व का चुनाव करेंगे।

सम्मेलन की तैयारी के लिए टाटानगर के विभिन्न उधोगों जैसे रेलवे, बैंक इंश्योरेंस, बीएसएनएल, पोस्टल राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के फेडरेशनों, किसानों, महिलाओं और लेखकों के जन संगठनों तथा शहर के प्रबुद्ध नागरिकों को लेकर एक व्यापक आधार वाली स्वागत समिति का गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन प्रतिष्ठित संस्थान एक्स एल आर आई के प्रोफेसर शांतनु सरकार बनाए गए हैं। सम्मेलन में प्रख्यात श्रमिक नेता व सीटू के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद तपन सेन, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष ज्ञान शंकर मजुमदार, कोल वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव डीडी रामानंदन, सीटू झारखंड के अध्यक्ष मिथिलेश सिंह, राज्य महासचिव प्रकाश विप्लव, कोल्हान इलाके मे सीटू के संस्थापक नेता के. के. त्रिपाठी के अलावा विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के विरादराना प्रतिनिधि भाग लेंगें।

सीटू राज्य सम्मेलन मे मुख्य फोकस शासक वर्ग द्वारा मजदूरों – कर्मचारियों के जीवन– जीविका पर किए जा रहे हमले, रोजगार का बढ़ता संकट, असंगठित क्षेत्र के कामगारों समेत ठेका और आउट सोर्सिंग मजदूरों को कम से कम 26 हजार रुपये मासिक न्युनतम वेतन, चारो श्रम कानून रद्द करने और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के अलावा नफरत की मुहिम के विरूद्ध सामाजिक सद्भाव के अभियान पर रहेगा। □

किसान बचाओ, गांव बचाओ, देश बचाओ

विकास के नाम पर बड़े कॉरपोरेट्स के हित में केंद्र सरकार लगातार किसान विरोधी नीतियां अपना रही है। एक तरफ अधिग्रहण के नाम पर जमीन हड़प रही है तो दूसरी तरफ कमरतोड़ महंगाई से खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ी है और बहुत कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। छोटे और मझौले किसान के लिए खेती बिलकुल अलाभकारी हो गई है, लिहाजा पूरे देश में किसान आंदोलनरत हैं। पिछले साल भर से चले अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन ने सरकार को तीन काले कानून वापस लेने को बाध्य तो किया लेकिन सरकार किसानों की माँग पर अभी भी चुप है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अगले कार्यक्रम की घोषणा भी की है।

झारखंड में आदिवासियों एवं अन्य गरीबों की पहचान जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई है। सीएनटी और एसपीटी कानून झारखंड में आदिवासी और अनुसूचित जाति के रैयतों को संवैधानिक सुरक्षा मुहैया कराता है। भाजपा नीत रघुवर सरकार ने पाँचवी अनुसूची एवं पेसा कानून में अवांछित संशोधन किए जिसका पुरजोर विरोध हुआ और रघुवर सरकार को इन संशोधनों को वापस लेना पड़ा।

झारखंड में कुल 35 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिसमें 10.5 लाख हेक्टेयर जमीन परती है। इसमें 20 लाख खेत मजदूर एवं 22 लाख बटाईदार को 5.5 लाख हेक्टेयर वन जमीन किसानों को पट्टे पर दी जा सकती थी। इस राज्य सरकार ने इसमें से सिर्फ 1.32 लाख हेक्टेयर जमीन पट्टे पर निर्गत किया लेकिन किसानों को उसमें भी अधिकांश जमीन पर बंदोबस्ती अभी तक नहीं मिली है। राज्य बनने के 22 वर्षों के बाद भी अभी तक सिर्फ 1.95 हेक्टेयर जमीन ही सिंचित है और इसमें भी बड़ी सिंचाई योजनाओं का कोई लाभ छोटे और मझोले किसानों को नहीं मिला है। लिहाजा किसान खेती के लिए लगभग पूरी तरह वर्षा पर आश्रित है और इसी लिए यहाँ खेती एक फसली है। वर्षा में थोड़ी देरी भी यहाँ सूखा का कारण बनती है। यहाँ एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसानों को ही मिलता है। बड़े बाँध और उद्योगों के लिए जमीन के नाम पर बहुत बड़ी संख्या में छोटे और मझोले किसानों को उनकी जमीन से बेदख़ल किया गया जिसका न उचित मुआवजा मिला है ना ही नौकरी मिली है। झारखंड में किसान की जोत का आकार 2–5 एकड़ इसीलिए वो अतिरिक्त अनाज नहीं उगा पाते हैं। झारखंड में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 80% किसान नहीं आते और झारखंड में सिर्फ 10% किसानों को ही कर्ज मिलता है। किसानों के लिए मंडी नहीं होने के कारण बिचौलिये भी उनको लूटते हैं। कुल मिलाकर देश से राज्य की तुलना करें तो झारखंड की स्थिति किसानों के लिए बहुत ज़्यादा खराब है।

झारखंड राज्य किसानों के मुद्दे पर लगातार आंदोलनरत है। 5 और 6 नवंबर को सिल्ली में झारखंड राज्य किसान सभा के राज्य सम्मेलन में भी इन मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी और आने वाले दिनों में इन पर ठोस कार्यक्रम भी लिए जाएंगे ताकि किसानों को आने वाले दिनों में हो कुछ लाभ मिल सके। □

अक्टूबर क्रांति आज भी प्रासंगिक

7 नवंबर 1917, मानव इतिहास का वह स्वर्णिम दिन, जब महान अक्टूबर क्रांति ने शानदार तरीके से सबसे पहली बार सर्वहारा राष्ट्र की स्थापना कर मार्क्सवाद–लेनिनवाद को शानदार तरीके से वस्तविक–सच के रूप में स्थापित कर दिया। कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में बोलशेविक पार्टी ने यह साबित कर दिया कि शोषक–पूंजीवादी व्यवस्था को क्रांति के माध्यम से मजदूर वर्ग के नेतृत्व में शोषित जनता द्वारा उखाड़ फेंका जा सकता है। अक्टूबर क्रांति सृजनशील और वैज्ञानिक "मार्क्सवाद–लेनिनवाद" के अवधारणा के प्रयोग का एक शाश्वत उदाहरण है, जिसका जीवंत सार है "ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण"।

अक्टूबर क्रांति से विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन को लगातार शिक्षा मिल रही है कि मजदूर–किसान गठजोड़ का महत्व, जनवादी केंद्रीयता के सिधांत से मजबूत हिरावल दस्ता के रूप में पार्टी की अपरिहार्य भूमिका, अनुशासित सर्वहारा वर्ग जिसका जनता से गहरा जुड़ाव, सफल क्रांति के अवश्यक आधार है।

मानव समाज की बहुत सारी उपलब्धियों का श्रेय अक्टूबर क्रांति को ही मिलता है। यूएसएसआर मे समाजवाद की स्थापना कर मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण का खात्मा, रोटी– कपड़ा– मकान के बुनियादी अधिकारों के जरूरतों की पूर्ति, जन्म से लेकर मृत्यु परंत सभी नागरिकों के जीवन को विकसित और समृद्ध करने कि सामाजिक दायित्व, पहली बार सभी को शिक्षा के द्वारा निरक्षरता को समाप्त करना, महिलाओं को घरेलू बेड़ी से से मुक्त कर बराबरी का हिस्सा एवम स्थान देना, पूंजीवादी देशों से बहुत पहले महिलाओं को राजनीति में बराबर की भागीदारी देना और आर्थिक सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मे स्थापित करना, समाज में मजदूरों की भूमिका को महत्व देना, उन्हें प्रशासनिक कार्य में आगे बढ़ाना और उनके काम के माहौल को उन्नत करना, उनके अधिकारों की रक्षा एवम विश्राम की व्यवस्था करना, सेवानिवृत्ति काल में भविष्य की सुरक्षा प्रदान करना, बेरोजगारी और मुफलिसी का खात्मा, वैज्ञानिक शोधों और प्रगति का इस्तेमाल पूरे समाज के उन्नति में लगाना,सभी को संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था की गारंटी, खेल की दुनिया में विशाल प्रगति करना।

हम प्रथम समाजवादी देश के अन्य उपलब्धियों का बयान करते हुए उनके तमाम विचलन, कमजोरी एवं गलतियां के प्रति सचेतन है। हमारी पार्टी ने इन सब को ध्यान रख कर शिक्षा लिया है ए आज जब मार्क्सवाद और समाजवाद के विचारधारा पर तीव्र हमला हो रहा है, तब अक्टूबर क्रांति के महत्व को बार–बार ध्यान रखना और ज्यादा जरूरी है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बदनाम किया जा रहा है। समाजवाद के असंख्य उपलब्धियों को नकार कर समाजवाद की तुलना घृणित फासीवाद और नाजीवाद से की जा रही है। हमारी मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टी का पुनीत कर्तव्य है कि इन तमाम कुत्साओ का कड़ा जवाब दे। हमारा दायित्व है कि इस सच को मजबूत किया जाए कि "शोषण –मुक्त समाज के लिये समाजवाद ही एक मात्र विकल्प, जरूरत और सच्चाई है, जिसे हासिल किया जा सकता है"।

9 मई 1945 को फासीवाद को ध्वस्त कर समाजवादी सोवियत रूस के लाल फौज ने रैहस्टाग पर लाल झंडा फहराकर विश्व शांति का रास्ता प्रशस्त किया दुनिया में साम्राज्यवाद के खिलाफ अभेद दीवाल खड़ा कर उपनिवेश व्यवस्था के खिलाफ भारत जैसे बहुत से देशों को राष्ट्रीय सार्वभौमिकता एवं मुक्ति आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, मुजफ्फर अहमद, जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रवादी कवि रविंद्र नाथ टैगोर ,सुब्रमण्यम भारती, नजरुल इस्लाम कथा सामाजिक कार्यकर्ता पेरीयार सरीखे महान लोगों को उदबुद्ध किया।

हाल फिलहाल में कोविड–19 महामारी के समय जहाँ समाजवादी देशों ने अपने और दूसरे देशों में बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा मे वैज्ञानिक शोध, औषधि, वैक्सीन, स्वास्थ सेवा में अतुलनिय सेवा प्रदान कर अपनी स्वच्छ श्रेष्ठता का जीता जागता प्रमाण पेश किया। उसी मानविय संकट के समय ने मुनाफा परस्त पूंजीवादी व्यवस्था का अमानविय और खोखला चेहरा उजागर कर दिया।

अक्टूबर क्रांति महान के 105 वीं सालगिरह पर कॉमरेड लेनिन और करोड़ों बोल्शेविक पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाल सलाम देते हैं , जिनकी संघर्ष और कुर्बानी ने विश्व में समाजवाद के स्थापित होने का रास्ता खोल दिया।

मार्क्सवाद–लेनिनवाद, समाजवाद, महान क्टूबर क्रांति जिंदाबाद, CPI(M) जिंदाबाद। □

– समीर दास

झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ का राज्य सम्मेलन

झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ का दो दिवसीय तीसरा झारखंड राज्य सम्मेलन 15 एवं 16 अक्टूबर को जामताड़ा में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन के पहले दिन सैकड़ों की संख्या में संघर्ष की पहचान लाल झंडा हाथों में लिए सेविका सहायिकाओं ने जामताड़ा शहर में एक विशाल जूलूस निकाला.

सम्मेलन का उदघाटन करते हुए मुख्य अतिथि और सीटू की राष्ट्रीय सचिव व ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्फर्स (आइफा) की राष्ट्रीय महासचिव ए0 आर0 सिन्धु ने कहा कि भाजपा शासित मोदी राज में कुपोषण बढ़ रहा है। महिलाओं और बच्चों को पोषण नहीं मिल रहा है। आईसीडीएस में आवंटन घटा दिया गया है। एक तरफ महंगाई के चलते सभी चीजों का दाम आसमान छू रहा है लेकिन आंगनबाड़ी मे पुराने रेट से ही पैसा दिया जा रहा है। झारखंड में बच्चों का खाना बनाने हेतु रसोई गैस के लिए एक बच्चा पर मात्र 13 पैसे प्रतिदिन दिया जा रहा है, जो साल भर मे एक गैस सिलेंडर का भी दाम नहीं है, जबकि जरूरत है 12 सिलेंडर का। पोषण ट्रेकर के नाम पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है जिसके खिलाफ एकजुट संघर्ष ही रास्ता है।

यूनियन की राज्य सचिव सावित्री सोरेन के द्वारा राजनीतिक सांगठनिक प्रतिवेदन पेश किया जिसमें उन्होनें रेखांकित किया कि लम्बे संघर्ष के बाद झारखंड सरकार ने सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाया और नियमावली बनाया गया। लेकिन इसमें भी त्रुटियां हैं. आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित रूप से मानदेय और पोषाहार का पैसा नहीं मिल रहा है। इसके खिलाफ सेविका सहायिका का राज्यव्यापी आंदोलन होगा।

समापन भाषण में सीटू झारखंड के महासचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि राज्य

शेष पेज 4 पर .....

हमारे धार्मिक .....

..... शेष पेज 1 से

प्रक्रिया इंसानो पर भी पूरी तरह लागू है। पावलोव को अपनी इस थ्योरी पर ६ 1904 मे नोबल पुरस्कार भी मिला।

शिक्षक अपने छात्रों को अच्छी आदतें सिखाने, और बुरी आदतें छुड़ाने के लिए इस थ्योरी का रोज प्रयोग करते हैं। बिस्तर पर छोटे बच्चे को सुलाने से पूर्व कहीं बच्चा सोते में बिस्तर पर पेशाब न कर दे की आशंका से माँ को उसे पहले ही पेशाब कराते देखा है? माताएँ बच्चों को सीटी की आवाज के साथ पेशाब कर देने के लिए अनुकूलित कर देती हैं। सुलाने से पूर्व वे उसे सीटी बजा कर पेशाब कराती हैं। सीटी का पेशाब से कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है। लेकिन बार–बार करने से बच्चा सीटी की आवाज, जो कि अप्राकृतिक उद्दीपन है, के विरुद्ध मूत्र विसर्जन करना, जो कि प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, करना सीख जाता है। ये अनुकूलन का साधारण सा बेहतरीन उदाहरण है।

अब आज के सामयिक ज्वलंत मुद्दे पर आते हैं। मानव विकास के क्रम में हमारे पूर्वजों ने करीब 5000 साल पूर्व धर्म, देवता, ईश्वर आदि की परिकल्पना करना प्रारंभ किया, तब से अब तक अनेक धर्म निर्मित किये। 300–400 वर्ष पूर्व का सिख धर्म सबसे नवीन मान सकते हैं। धर्म मनुष्य को 5000 साल से अप्राकृतिक उद्दीपन के प्रति प्राकृतिक प्रतिक्रिया करने के लिए अनुकूलित करते रहे हैं। हमारे धर्मों के प्रति हमारी आस्था, सम्मान, विश्वास, धैर्य, शांति प्राप्ति जैसी सभी प्रतिक्रियाएं एक अप्राकृतिक उद्दीपन के प्रति प्राकृतिक प्रतिक्रिया मात्र हैं।

जब मंदिर की घंटी की आवाज सुन किसी हिन्दू का मन श्रद्धा से भर जाता है, जब किसी फजिर की अजान के साथ किसी मुस्लिम का सब दर्द, नींद, मौसम के साथ लड़ाई सब कुछ मिट जाता है और वह वुजू कर श्रद्धा से नमाज हेतु तैयार हो जाता है, जब कोई कैथोलिक क्रिस्चियन दर्द से बचने की अपनी प्राकृतिक प्रतिक्रिया के विपरीत जीसस की तरह खुद को सूली पर चढ़ा कर कर सुख और संतोष प्राप्त करता है तो वो अप्राकृतिक उद्दीपन के प्रति प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं करता ही दिखाई देता है।

हमारे धार्मिक समूह, समाज, परिवार, समुदाय, धार्मिक साहित्य, ग्रंथ, संस्कृतियां, पर्यावरण, माता–पिता, शिक्षा व्यवस्था आदि सब ऐसे डिजाइन की गई हैं कि छोटे बच्चों को जाने–अनजाने इन अप्राकृतिक उद्दीपन के प्रति प्राकृतिक प्रतिक्रिया करने के लिए अनुकूलित कर देते हैं, और फिर 'वो' एक 'भक्त' बन जाता है।

मानव सभ्यता में ये काम 5000 साल से लगातार हो रहा है। बस कुछ लोग ही इस अनुकूलन से अपने प्रयासों से बाहर निकल पाते हैं। ऐसे बाहर निकले लोगों ने या तो कोई नया धर्म ईजाद कर दिया और वे खुद नए पैगम्बर बन गए या वे नवीन सत्यों को उजागर करने वाले अन्वेषणकर्ता बने, वैज्ञानिक बने।

आज ऐसे व्यक्ति को दुनिया नास्तिक, काफिर, धर्म विरोधी और पागल समझती है। आप इतिहास पर नजर डालिये चार्वाकों, बुद्ध, महावीर, मूसा, ईसा, मोहम्मद के साथ तत्कालीन स्थापित धर्मों, यथास्थितिवादियों और परंपराओं ने कैसा सुलूक किया था। गैलीलियो और कोपरनिकस के साथ भी तत्कालीन धार्मिक लोगों के व्यवहार को याद कीजिये।

दरअसल हमारा धार्मिक और जातीय समूह पावलोव के अनुकूलित पालतू जीव की प्रजाति के समान ही अनुकूलित है जो 5000 साल के सतत अनुकूलन के बाद बनावटी उद्दीपन के विरुद्ध एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया करने का अभ्यस्त हो गया है। अब 'वो' मतारोपित है, अभिशप्त है, कुछ अधिक नहीं सीखना चाहता, न खोजना चाहता है, न आगे बढ़ना चाहता है, न जानना चाहता है।

मजेदार बात है कि यदि, हमारा–अर्जित ज्ञान इस प्रकार के कृत्रिम उद्दीपनो के अनुकूलन के स्रोत आया है, तो हमारा–अर्जित ज्ञान सत्य–परख या तर्क–संगत ना होकर "भ्रामक–ज्ञान" भी हो सकता है।

हमारे देश मे भी गोदी मिडिया निरंतर झूठी खबरों को परोसकर समाज मे "फरेब के अनुकूलन की प्रक्रिया को तेज कर रहा है"। इसके विपरीत हम अपने मूल स्वभाव के अनुसार सत्य–परख या तर्क–संगत होकर इन अप्राकृतिक अनूकलन के अनुशरण मे जाने से बचकर प्रगतिशील रास्ते पर चल सकते हैं। □

महिलाएं और .....

..... शेष पेज 1 से

पूंजीवादी व्यवस्था में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू तथा श्रम के कई अन्य रूपों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। घर की देखभाल, बच्चों का पोषण व उनकी परवरिश जैसे अनेक काम अवैतनिक होते हैं, जो सामाजिक श्रम में महिलाओं की भूमिका व और उनके आर्थिक स्तर को कमतर बनाते हैं।

दूसरे शब्दों में, यह मुनाफे पर आधारित व्यवस्था को चलाने का परिणाम है जिसके मुनाफे की दर श्रम की कीमत गिराने से बढ़ती है। समाज अपने भीतर गरीबी व शोषण के ढेरों ऐसे मामले छिपाये होता है जो तुरंत निगाह में नहीं आते। जीवन का अधिकांश वक्त, शहरी गरीब जनता, किसान, मजदूर, कर्मचारी तथा निम्न बुर्जुआ वर्ग अतुलनीय संकटों में रहकर काटते हैं और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही लगाते हैं। ऐसे परिवारों की लाखों महिलाएं घरेलू नौकरों की तरह रहती हैं, जो हर संभव प्रयास करके, एक एक पाई बचाकर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ऐसी महिलाओं को ही पूंजीपति घरेलू नौकरानियों के रूप में काम पर रखते हैं और ये खुद व अपने परिवार के लिए रोटी के टुकड़े से थोड़ा अधिक कमा लेने की उम्मीद में अत्यधिक निम्न मजदूरी पर काम करने को तैयार भी हो जाती हैं।

एक तरफ खाते–पीते घरों की महिलाओं की जिंदगी घरेलू नौकरों, फैशन तथा शादी–विवाह समारोहों आदि के बारे में चर्चा करते हुए बीतती है, जो सम्पत्ति, सामाजिक स्तर, नौकरी अथवा उद्यम के सापेक्ष स्तरों में निर्धारित होता है, जो टीवी सीरियलों की मुख्य पटकथाएं तथा नाटकों द्वारा समाज में औरतों की एक खास छवि पर आधारित होता है। आगे चलकर धार्मिक कट्टरपंथी इसी आधार पर महिलाओं का कथित 'चरित्र चित्रण' करते हैं। वे महिला को सतीत्व, शक्ति और शील से जोड़ कर एक तरफ पूज्य दिखाते हैं तो दूसरी तरफ समाज से पूरी तरह से उसे काट कर उसका हर तरह से शोषण करते हैं और उसके शोषण के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराते हैं और उसका बहिष्कार तक करते हैं। ये सब इस शोषणकारी समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी भूमिका को जबरदस्ती निर्धारित करने की कवायद होती है।

महिलाओं की गुलामी की जंजीरें, जिसमें वे जकड़ी हुई हैं, तभी तोड़ी जा सकती हैं जब श्रम के मायने परिवर्तित हो जाएंगे, जब उत्पादन के साधन बदलेंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े देश में एक महिला की आजादी वहाँ से शुरू होती है जब उसे घरेलू इस्तेमाल के लिए दूर से बाल्टियों में पानी भर के लाने के बजाय रसोई घर की टोंटी से पानी मिलने लगे, प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से घरेलू श्रम को आसान किया जाए, सामूहिक रसोई घरों और शिशु पालन केंद्रों का निर्माण हो।

घरेलू हिंसा के अधिकतर मामले आर्थिक मुद्दों से जुड़े होते हैं, अतः बदहाली और भयानक तंगी भरे इस समाज में ये खत्म नहीं हो सकता। फैक्ट्रियों तथा अन्य संस्थानों में महिला श्रमिकों को पुरूषों की तुलना में कम पगार मिलती है। आय असमानता से लेकर वेश्यावृत्ति तक, औरतों के जीवन का मूल अभिशाप यह शोषक वर्ग व्यवस्था है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे हर स्तर तक खून चूसने वाली जोकें भरी पड़ी हैं। पितृसत्तात्मक समाज द्वारा थोपी गयी वर्जनाएं, मान्यताएँ, खोखले मूल्य और नैतिकताएं जान बूझ कर इस तरह बनायी गयी हैं जिससे मेहनतकश औरतों के शोषण को निर्बाध ढंग से जारी रखा जा सके।

झारखंड में भी महिलाओं की स्थिति कुछ अलग नहीं है। विकास के नाम पर विस्थापन और छँटनी का मुख्य दंश झेलती,नौकरी के नाम पर गैरकानूनी प्रवासन में अमानवीय यातना झेलती, परिवार का पेट पालनेको किसी भी मजदूरी पर घरेलू नौकर का काम करती महिलाओं की स्थिति दयनीय है। कुपोषण, खून की कमी, अशिक्षा, बेकारी, सामाजिक–आर्थिक शोषण आदि बुरी तरह प्रभावित महिलाएँ डायन–बिसाही जैसी धार्मिक कुरीतियों के नाम पर जान तक गवां बैठती हैं।

इस कुव्यवस्था को खत्म करने का एक मात्र तरीका है – वर्ग संघर्ष, जहाँ मेहनतकश पुरूषों व महिलाओं को मिल कर इसे उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। इस क्रम में कोई भी अन्य प्रवृत्ति, जो इस वर्गीय एकता को भंग करती हो, चाहें वह नारीवाद हो, राष्ट्रवाद हो, धर्म या फिर अन्य कोई पूर्वाग्रह जैसे प्रतिक्रियावादी तथा प्रतिगामी प्रवृत्ति को पूरी तरह त्याग कर वर्गीय चेतना से लैस हो कर तीखे वर्ग संघर्ष में उतरना होगा। एडवा के बैनर तले झारखंड में महिलाएँ लगातार संघर्षरत हैं। □

चौपाल

"रमेश कितना नालायक निकला, सिंह जी का लाखों रुपया पॉलिटिक्स में डूबा दिया। सिंह जी की भी मति मारी गई थी जो बेटा को मुखिया बनाने चले थे। रिटायरमेंट वाला पैसा भी इसी में स्वाहा हो गया। अब विलाप कर रहे हैं।हमने बताया था कि अभी घोर कलियुग चल रहा है, अभी शूद्रों का समय है, अब देखिए कृष्णा जीत गया ना! सब ने एकतरफा वोट दे दिया उसको, "पंडित जी बोले जा रहे थे।

"तो क्या करते पंडित जी? हमसे कृष्णा–त्रिशना की जी हजूरी नहीं होगी! जिसको सामने बैठने की औकात नहीं, उसको माथा पर कैसे बिठाते? हमारे पूर्वज हमको कभी माफ करते, "सिंह जी बैठते हुए बोले!

"अब तो कृष्णा मुखिया बन गया! लेकिन बिना हमलोग के डायरेक्सन के वो क्या कर सकेगा? पॉलिटिक्स का "प" भी उसको नहीं आता। अब हमलोग उसको बताएँगे पॉलिटिक्स कितनी कुत्ती चीज है। ऐसा चक्कर–घिन्नी में उसको फँसाएँगे ना कि नाम उसका रहेगा और काम सब हमलोगों को मिलेगा", साहूजी चहके। "हाँ साहूजी, कुछ किया जाए, छोड़ना तो नहीं है", पंडित जी बोले। सिंह जी की भी सहमति थी। सब चौपाल की ओर चल पड़े, आज कृष्णा का सम्मान हो रहा था वहाँ।

"नमस्कार! मैं आप सब का कृष्णा, अपने आपको आपकी सेवा में सपर्पित करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ माँगना चाहता हूँ! (तालियाँ) तालियाँ किसलिए, अभी मैंने किया ही क्या है? ... होश सम्भालने के बाद से ही वर्जनाओं से दो–चार होता रहा हूँ! ये मत करो, वहाँ मत जाओ, इनके पैर पड़ो, वहाँ हाथ जोड़े खड़ा रहना आदि। बचपन गँवाना, धूप में देह तपाना, स्वास्थ्य लुटाना, कामचलाऊ शिक्षा पाना, भोजन कमाना आदि ही मेरी नियति थी। धर्म, साफ–सफाई और दक्षिणा देने तक सीमित था तो राजनीति बड़ों के कहे अनुसार वोट देने तक सीमित! "बड़ों" के दिए संस्कार और विचार से परे सोचना भी अपराध जैसा था", कृष्णा का स्वर तल्ख था।

"संविधान ने कुछ बदलाव दिए लेकिन विभेदकामी सोच की खाई बनी रही। एक खतरनाक वृति सामने आई ... राजनीति बेकार है, राजनीति से दूर रहो! ये जम कर प्रचारित भी किया गया। ये सचमुच बहुत खतरनाक है। अच्छे लोग राजनीति से दूर हो गए और सत्ता लोभी राजनीतिक दलों की गिरोहबंदी शुरू हुई जो अब चरम पर है और हमारे लोकतंत्र के लिए ही खतरा बन चुकी है! और तुर्रा ये है कि राजनीति को ही इसके लिए दोषी भी ठहराया जा रहा है", कृष्णा का स्वर संयत था।

"मैं चाहता हूँ कि हम सब राजनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।और क्यूँ नहीं? आखिर, राजनीति है क्या? राजनीति दो शब्दों से बना है राज और नीति। राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने का तौर–तरीका। आप सोचिए, बिना अनुशासन और उचित नीतियों के कार्यान्वयन के क्या व्यक्तिगत प्रगति संभव है? क्या कोई परिवार बिना सही नीतियों के आगे बढ़ सकता है और क्या आप सब हमारे समाज को सुशासन और सही नीतियों में बिना अपनी सक्रिय सहभागिता के बदल सकते हैं? बिलकुल नहीं! यही देश और विश्व पर भी लागू होता है", कृष्णा उपस्थित जनो से मुखातिब था।

"हम क्या कर रहे हैं? सत्ता लोभी राजनीतिक गिरोह, जिनको हमसे हमारे वोट के सिवा और कोई मतलब नहीं, हमारे मुद्दे तय करते हैं, उम्मीदवार थोपते हैं, हमारे विरुद्ध ही नीतियाँ बनाते हैं और अपना कुशासन और कुव्यवस्था हम पर थोपते हैं। हमारे मुद्दे, हमारी समस्याएँ, हमारे सवाल, और खुद हमलोग उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। झूठे वादे, झूठे सपने, आरोप–प्रत्यारोप और अनर्गल मुद्दों पर भावनात्मक चक्रव्यूह रच कर धर्म–जाति–वर्ग आदि में हमें बुरी तरह से बाँट कर ये हमारा वोट और हमारे सपने, दोनो छीन लेते हैं! और हम राजनीति को गाली देकर इनके लिए मैदान खाली कर देते हैं। नतीजा इनकी लगातार दीवाली और अपना लगातार दिवाला! ये लोकतंत्र की वास्तविक अवधारणा 'जनता का जनता द्वारा जनता के लिए' के बिलकुल विपरीत है! जनता का राजनीति से बढ़ता ये दुराव हमारी बदतर होती स्थिति और शासन की बढ़ती निरंकुशता का मुख्य कारण होता है। अतः मेरा आप सब से करबद्ध निवेदन है कि शोषण–अस्पृश्यता का खात्मा करने और मुझ तक को निरंकुश बनने से बचाने के लिए राजनीति को अपने जीवन में हर स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुद्दों के चयन और योजनाओं के कार्यान्वयन में सक्रिय सहभागिता रखें और व्यवस्था पर अंकुश रखें।एक नागरिक के तौर पर ये आपका प्रमुख संवैधानिक दायित्व भी है।", कृष्णा हाथ जोड़े खड़ा था। साहू जी के तोते उड़ चुके थे, सिंह जी मायूस थे, पंडित जी बुदबुदा रहे थे ...घोर कलियुग है... □

सरकारी स्कूलों को बंद करने का फरमान

आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के समय हमारे देश की साक्षरता दर 12 फीसदी थी। महिलाओं की साक्षरता दर तो मात्र 8 फीसदी थी। अतः एक कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट के तहत सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करने की बात की गई लेकिन केंद्र एवं राज्य सरकारों ने शिक्षा में बजटीय आवंटन इतना कम रखा कि 2014 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर मात्र 74.03 % है ।

नवउदारवादी आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद अन्य उद्योगों एवं सेवा के अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा में भी बड़े पैमाने पर निजीकरण एवं निगमीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को घाटे की सौदा बनाया गया। शिक्षकों के रिक्त पदों को नहीं भरा जाने लगा और उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुबंध पर तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पारा शिक्षकों की नियुक्ति की जाने लगी। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ होने लगा। इसके विपरीत निजी शिक्षण संस्थानों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया। आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चे निजी विद्यालयों में दाखिला लेने लगे जबकि आम जनता के बच्चे, जो दो वक्त की रोटी की जुगाड़ में ही परेशान था, सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता में आई कमी के कारण शिक्षा से वंचित होने लगे। स्कूलों में बच्चों की कमी दिखलाकर सरकारी स्कूलों को बंद किया जाने लगा।

हमारे राज्य झारखंड में लगभग 4700 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। लगभग 30% प्राथमिक विद्यालयों में एकल शिक्षक व्यवस्था है। बंद होते सरकारी स्कूलों से सबसे अधिक प्रभावित गरीब मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे हुए हैं। गाँवों से प्राथमिक विद्यालयों के बीच की दूरी बढ़कर डेढ़ से दो किलोमीटर की हो गई है और दुर्गम पहाड़ी और जंगली इलाकों में बच्चों के लिए यह दूरी तय करना मुश्किल ही नहीं खतरनाक भी हो गया है। इसलिए स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन नीतियों से झारखंड में भी स्कूली घनत्व बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड के रंगरलिया पंचायत के पत्थर चला गाँव में 1953 ई. में स्थापित प्राथमिक विद्यालय आज बंद हो चुका है जिसके चलते बच्चे पढ़ाई छोड़ने को बाध्य हो गए हैं ।

हरियाणा सरकार द्वारा निजी विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाने पर प्रति बच्चा प्रति माह ₹500 देय होगा और अगर निजी स्कूल में पढ़ता है तो उसके अभिभावक को प्रति बच्चा प्रति माह ₹1100 रुपए राज्य सरकार से मिलेगा। इस तरह पैसे का लालच देकर सरकार गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजना चाहती है, ताकि सरकारी स्कूलों को बंद करके कॉरपोरेट घरानों को प्राथमिक से लेकर उच्चतर सरकारी शिक्षण संस्थानों को औने–पौने दामों में बेचा जा सके। इसके लिए पूंजी का खेल भी शुरू हो गया है।

ऐसी स्थिति में बिहार और झारखंड में जहां सामाजिक एवं आर्थिक विषमता की खाई अभूतपूर्व है, इन नीतियों से बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। कोविड महामारी के दौरान जब विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जा रही थी, ज्ञान विज्ञान समिति, झारखंड ने पाया कि 87% बच्चों के पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। अतः समिति ने झारखंड के 5 जिलों के 15 प्रखंडों के 100 पंचायतों में वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के तहत सामुदायिक शिक्षण केंद्र "खेत–खलिहान में शिक्षा" शुरू किया था। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के 5 पंचायतों में ऐसे 62 केंद्र स्थापित हुए थे। किंतु, यह शिक्षा का ठोस विकल्प नहीं हो सकता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी है कि सरकार इसकी पूरी जिम्मेदारी ले। हमारे देश में 2009 में 'शिक्षा का अधिकार' कानून बनाया गया। परंतु, अन्य सभी कानूनों की तरह यह कानून भी बेमानी हो गया है। 20,000 की आबादी पर स्कूल खोलने की नीति की जगह अब 30,000 की आबादी तक स्कूल बंद किए जा रहे हैं।

हेमंत सरकार का रूख भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति सकारात्मक नहीं है। केंद्र सरकार की प्रस्तावित जनविरोधी शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में वो आगे बढ़ रही है और शिक्षा बजट में वृद्धि के विरुद्ध है। अतः हमारे सामने जनविरोधी शिक्षा नीतियों और क्रियाकलापों के विरुद्ध संघर्ष तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। □

– काशी नाथ चटर्जी और कुमार सत्येन्द्र

झारखण्ड राज्य .....

..... शेष पेज 3 से

में आंगनबाड़ी कर्मियों को अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। केंद्र की भाजपानीत मोदी सरकार के द्वारा निजीकरण के रास्ते देश को गुलाम बनाया जा रहा है। देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। करोड़ों लोगों का रोजगार छीन गया है। नई शिक्षा नीति से गरीबों के बच्चे उच्च शिक्षा से दूर हो जाएंगे और शिक्षा मुठ्ठी भर लोगों के लिए रह जाएगा। मजदूरों के अधिकारों को छीनने के लिए 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर चार लेबर कोड में बदला जा रहा है। आज योजना कर्मियों सहित मजदूर वर्ग को सरकार की इस गुलाम बनाने वाली नीतियों के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है.

सम्मेलन में 35 सदस्यीय नई राज्य कमिटी का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया जिसमें मीरा देवी, सावित्री सोरेन एवं लखन लाल मंडल क्रमशः अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष चुने गए। संजय

पाठकों को सूचना .....

जन जोहार मीडिया अब

पर भी उपलब्ध है।

पार्टी कोष में सहयोग की अपील

संघर्ष कोष के लिये स्वेच्छा से निम्नलिखित बैंक खाते में अपना योगदान करें।

Communist Party of India Marxist
Bank : Bank of Baroda
Main Branch, Ranchi
A/c No. : 00170200000219
IFSC Code : BARB0RANCHI

सीपीआई (एम) राज्य कमिटी, झारखण्ड की ओर से राज्य सचिव प्रकाश विप्लव द्वारा संपादित एवं प्रेषित।
माकपा पार्टी कार्यालय : विश्वकर्मा मंदिर लेन, मेन रोड, रांची–834001, वेबसाईट : cpimjharkhand.org, ई–मेल : janjohar.jharkhand@gmail.com